Title:Need to provide adequate financial assistance to Government of Bihar for proper water-management in the State-laid.

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, बिहार के बंटवारे के बाद, अब बचे बिहार को खान और खनिज के स्थान पर खेतों के खाद्यान्न पर ही निर्भर होना होगा। परन्तु अभी यहां के खेतों में खाद्यान्न कम और खर-पतवार का ही बाहुल्य है। इस हालात को तुरन्त बदलने की जरूरत है और इसीलिए जल के प्रबंध की सुयोग्य व्यवस्था लाजमी है। शेा बिहार के क्षेत्र में अभी तक के आक्कलन के अनुसार 53.530 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकता है, किन्तु अभी तक मात्र 26.170 लाख हेक्टेयर भूमि को ही सिंचित व्यवस्था में लाया जा सका है। इसी प्रकार जल जमाव से 63.31 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित है, किन्तु 29.28 लाख हेक्टेयर, भूमि में से ही अतिरिक्त जल निकास की व्यवस्था की जा सकी है। एक आक्कलन के अनुसार उपरोक्त दोनों समस्याओं के समाधान हेतु 66,500 करोड़ रूपये की फिलहाल लागत होगी। बिहार जैसे साधनहीन, निर्धन राज्य के लिये इतनी बड़ी राशि अपने बूते पर जुटा पाना बिल्कुल संभव नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त राशि की व्यवस्था बिहार राज्य के लिए कर दे, ताकि बिहार राज्य को जल की सुव्यवस्था कर विनाश से बचा कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके।